प्रसार भारती
आकाशवाणी शिमला
05.04.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

"आज के मुख्य समाचार"

- प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का लिया निर्णय।
- केंद्र ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल को एक सौ 36 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा–वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित होने से गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ।
- मुख्यमंत्री ने ठियोग के सरा गड़ाकुफर में एक करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का किया शिलान्यास।

कैबिनेट

राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई जिन्होंने चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। मंत्रिमंडल ने 3 सौ 82 मैगावाट सुन्नी, 2 सौ 10 मेगावाट लुहरी चरण एक और 66 मैगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को भी मंजूरी प्रदान की जो पहले एसजेवीएनएल को आवंटित की गई थीं। बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मौजूदा मासिक वजीफा बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का फैसला किया गया। इसी तरह सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के लिए वजीफा एक लाख 30 हजार रुपये प्रति माह किया गया है। मंत्रिमंडल ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप–समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमडंल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

आपदा राहत

केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को अतिरिक्त एक हजार दौ सौ 80 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता को मंजूरी दी है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से हिमाचल प्रदेश को एक सौ 36 करोड़ 22 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। गृह मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि सरकार ने आपदाओं के बाद इन राज्यों में तत्काल मंत्रालय स्तर की केंद्रीय टीमों को भेजा था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2024–2025 में 28 राज्यों को राज्य आपदा

प्रतिक्रिया कोष के तहत बीस हजार दौ सौ 64 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं और 19 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से पांच हजार एक सौ 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 19 राज्यों को लगभग पांच हजार करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से आठ राज्यों को 7 सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को समयबद्ध व गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और निगम के बेड़े में जल्द ही 6 सौ नई बसें शामिल की जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इनमें 3 सौ 50 इलैक्ट्रिक बसें और 2 सौ 50 डीजल बसें शामिल हैं।

जगत सिंह नेगी

वन अधिकार अधिनियम विषय पर आज सोलन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन भूमि में लोगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रयासरत है ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में वन अधिकार समितियां गठित करना अनिवार्य है।

कार्यशाला में शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सोलन के विधायकों सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज श्री दुर्गा अष्टमी के पावन आवसर पर राजभवन शिमला में फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वे पिछले 34 वर्षों से नवरात्रों के दौरान फलहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी ऐसे अवसरों पर लोगों को जोड़ने का प्रयास है ताकि देव भूमि को दिव्य बनाया जा सके।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने कहा कि ये बिल लाकर केंद्र सरकार ने गलत नियम को सही किया है। राज्यपाल ने कहा कि वक्फ कानून में नए प्रावधानों से गरीब मुसलमान को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला में ठियोग क्षेत्र के सरा गड़ाकुफर में एक करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद सरा गड़ाकुफर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विश्राम गृह की सुविधा नहीं है, जिसे देखते हुए सरकार ने इस स्थान पर वन विश्राम गृह खोलने का निर्णय लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए ईको–टूरिज्म साइटस को चयनित कर उनका आबंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 7 ईको–टूरिज्म साईट्स आवंटित की गई हैं। इसके अलावा 78 नई ईको–टूरिज्म साईट्स की आवंटन प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ कर दी जाएगी।

राजेश धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं में राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेले की अध्यक्षता की। यह ग्रीष्मोत्सव 5 से 9 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, खेलकूद प्रतियोगिताएं और जन–जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं का यह मेला करीब 40 वर्षों से आयोजित हो रहा है और समय के साथ इसका स्वरूप और महत्व लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मेला स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है, जिसमें सीर खड्ड के दोनों किनारों को संवारा जा रहा है।

विक्रमादित्य सिंह

दुर्गाष्टमी के मौके पर आज लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता और प्रदेश के छ बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के नाम पर राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का गठन किया किया है। उन्होंने कहा कि ये संस्था 23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर शिमला के रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन वीरभद्र सिंह की सोच को आगे बढ़ाने का काम करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल व नशे की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया

कि प्रतिमा का पूरा खर्च संस्था द्वारा वहन किया जाएगा और संस्था के माध्यम से गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का लिया निर्णय।
- केंद्र ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल को एक सौ 36 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा–वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित होने से गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ।
- मुख्यमंत्री ने ठियोग के सरा गड़ाकुफर में एक करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले वन विश्राम गृह का किया शिलान्यास।